गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 201
दि. 22.11.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर: नीतीश के शांत कमरे से निकलकर सम्राट चौधरी के हाथों में पहुंची ताकत की चाबी

(जीएनएस)। पटना की राजनीति इन दिनों किसी पुराने महाकाव्य की तरह लग रही है, जिसमें लंबे समय से चला आ रहा संतुलन अचानक टूटता दिखाई देता है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। बीस साल से अधिक समय से बिहार में सत्ता का एक स्थायी चेहरा रहा—नीतीश कुमार—जिनके पास प्रशासन की धुरी घूमती थी। मुख्यमंत्री का पद उनके हाथों में चाहे कितनी भी बार गया और आया हो, लेकिन सरकार की वास्तविक रीढ़ यानी गृह विभाग हमेशा उनके ही संरक्षण में रहा। पुलिस तंत्र, खुफिया इकाई, कानून-व्यवस्था, जिले के कप्तानों के तबादले, बड़े मामलों की जांच—इन सब पर अंतिम हस्ताक्षर हमेशा मुख्यमंत्री आवास से ही निकलते थे। लेकिन इस बार का राजनीतिक दृश्य इस परंपरा को तोड़कर कुछ नया लिखता दिखाई दे रहा है, और यही बदलाव पूरे बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है।

गठबंधन सरकार के गठन के साथ ही विभागों के बंटवारे की सूची सामने आई, और उसी सूची में वह निर्णय छिपा था जिसने पूरे राज्य की राजनीतिक धड़कन तेज कर दी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम के सामने जब "गृह विभाग" लिखा हुआ दिखा, तो वह सिर्फ एक सूचना नहीं थी—वह एक युगांतकारी बदलाव का संकेत था। बिहार के राजनीतिक समीक्षक इसके वजन को भली-भांति समझते हैं। गृह विभाग का मतलब है राज्य की सुरक्षा मशीनरी पर नियंत्रण, पुलिस की नीति, बड़ी घटनाओं पर राज्य की प्रतिक्रिया, और सबसे महत्वपूर्ण—सत्ता की असली चाबी।

अब यह चाबी पहली बार मुख्यमंत्री के हाथों से निकलकर किसी और के पास

चली गई। और यह 'किसी और' का व्यक्तित्व भी साधारण नहीं है। सम्राट चौधरी बीजेपी के उभरते हुए नये ध्रुव हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के भीतर तेजी से उभरे हैं। उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अगर गृह विभाग सौंपा गया है, तो यह उन पर सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि आने वाले समय में वे बिहार की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा बनने जा रहे हैं। राजधानी के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि बीजेपी अब बिहार में सिर्फ सहायक दल बनकर नहीं रहना चाहती; वह अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान गढ़ने की लंबी योजना पर काम कर रही है। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए जिस 'अवध' और 'मगध' जीतने की बात पार्टी रणनीति में शामिल है, यह फैसला उसी का अगला कदम है।

पटना के सत्ता गलियारों में इस बदलाव को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे नीतीश कुमार की मजबूरी मानते हैं, तो कुछ इसे बीजेपी की रणनीतिक जीत। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संतुलन की राजनीति रही है। वे गठबंधन के समीकरणों को ऐसे साधते रहे हैं कि सत्ता और नियंत्रण दोनों उनके हाथों में रहें। लेकिन इस बार के समीकरणों में बीजेपी ने अपनी ताकत पहले से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ाई है। चुनाव बाद परिस्थितियां जिस तरह बनीं, उसमें नीतीश को बीजेपी की मांगों के आगे झुकना पड़ा या फिर यह एक सोची-समझी मौन सहमति थी—यह बात अब तक अस्पष्ट है, लेकिन नतीजा साफ है कि सत्ता का एक बड़ा हिस्सा अब मुख्यमंत्री की मेज से उठकर उपमुख्यमंत्री की दस्तक पर पहुंच गया है।

सरकार का यह चेहरा बदलता है तो प्रशासन का पूरा चरित्र बदलता है। पुलिस अधिकारियों की बैठकों का केंद्र अब सिर्फ 'वन अणे मार्ग' नहीं रहा, बल्कि उपमुख्यमंत्री का कार्यालय भी उतनी ही सक्रियता से बुलाया जाने लगा है। फाइलों का प्रवाह बदला है, आदेशों का स्वर बदला है, और सरकार की गति भी बदली हुई दिखाई देती है। अधिकारियों के बीच यह चर्चा आम है कि आने वाले महीनों में बिहार प्रशासन में "दो पावर सेंटर" का मॉडल और स्पष्ट रूप से दिखेगा। यह मॉडल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम के बीच नया समीकरण तैयार करेगा, और इसका असर राज्य की राजनीतिक दिशा पर लंबे समय तक रहेगा।

उधर विभागों के बंटवारे में अन्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अरुण शंकर को पर्यटन और कला, विजय कुमार सिन्हा को भूमि-राजस्व व खनन, दिलीप जायसवाल को उद्योग, मंगल पांडेय को स्वास्थ्य व विधि, रामकृपाल यादव को कृषि, नितिन नबीन को सड़क निर्माण विभाग, संतोष सुमन को लघु जल संसाधन, संजय टाइगर को श्रम संसाधन, दीपक प्रकाश को पंचायती राज, सुरेंद्र मेहता को पशु संसाधन व मत्स्य, रमा निषाद को पिछड़ा-अतिपिछड़ा कल्याण, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन और एलजेपी (आर) को लोक स्वास्थ्य व गन्ना उद्योग का विभाग दिया गया है। लेकिन इन विभागों पर न तो वैसा राजनीतिक तापमान है, न वैसी चर्चा—क्योंकि उनका प्रभाव सीमित दायरे में है। वास्तविक हलचल एक ही फैसले के कारण है—गृह विभाग।

बिहार के आम लोगों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्ष तक सभी इसे एक संकेत के रूप में देख रहे हैं। बीस सालों में पहली बार सत्ता की धारा अपनी परंपरागत दिशा बदल रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठा है, लेकिन सत्ता की सनक, उसकी नब्ज, उसकी धड़कन अब एक नई जगह महसूस हो रही है। यह वह स्थिति है, जहाँ से एक नए नेतृत्व के उदय की शुरुआत होती है। इतिहास ऐसे ही पलों को याद रखता है—जब कोई सत्ता का बड़ा निर्णय अगले दशक के राजनीतिक चेहरे को जन्म देता है।

बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ पुरानी परंपराएँ नए प्रयोगों से टकरा रही हैं। आने वाले समय में यह लड़ाई सिर्फ विभागों की नहीं, बल्कि प्रभाव, नियंत्रण और राजनीतिक भविष्य की होगी। और यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि इस लड़ाई में सम्राट चौधरी अब एक निर्णायक पात्र बन चुके हैं।

जिंक-आयन बैटरियों में भारत की बड़ी छलांग: नई तकनीक से खुल सकता है लिथियम का विकल्प

(जीएनएस)। बेंगलुरु से आई एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि ने ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। भारतीय शोधकर्ताओं ने जिंक-आयन बैटरियों को इतना उन्नत बनाने में सफलता हासिल की है कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक लिथियम-आयन बैटरियों का मजबूत और किफायती विकल्प बन सकती है। ऊर्जा सुरक्षा, बैटरी लागत और पर्यावरणीय जोखिमों पर चल रही वैश्विक चिंताओं के बीच यह खोज भारत के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

यह शोध बेंगलुरु के सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज में विकसित किया गया, जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से वैज्ञानिकों की एक टीम महीनों तक इस परियोजना पर काम करती रही। टीम का नेतृत्व डॉ. अशुतोष कुमार सिंह ने किया, जिनके मार्गदर्शन में शोधकर्ताओं ने कैथोड सामग्री में एक ऐसा सूक्ष्म परिवर्तन किया जिसने पूरी बैटरी की क्षमता को नई

ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया। वैज्ञानिकों ने वैनाडियम ऑक्साइड नामक पारंपरिक कैथोड सामग्री को एक विशेष ताप–विद्युत रासायनिक तकनीक से गुजारा, जिसके बाद इसकी आंतरिक संरचना ऐसी बन गई कि यह अधिक ऊर्जा संचित करने और उसे तेजी से प्रवाहित करने में सक्षम हो गई।

शोध टीम के कर्मचारियों के अनुसार परिवर्तन भले ही प्रयोगशाला स्तर पर किया गया हो, लेकिन इसका प्रभाव बैटरी के प्रदर्शन में अत्यंत स्पष्ट दिखाई दिया। जिंक-आयन बैटरियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये लिथियम की तुलना में न केवल अधिक सुरक्षित होती हैं, बल्कि इनके निर्माण में उपयोग होने वाला जिंक सस्ता, आसानी से उपलब्ध और पुनर्चक्रण योग्य धातु है। नई तकनीक ने इन बैटरियों की चार्जिंग गति को बेहतर बनाया, लंबे समय तक क्षमता बनाए रखने में मदद की और ऊर्जा घनत्व को भी बढ़ाया। यह वे सभी गुण हैं जिनके अभाव में जिंक-आयन तकनीक अब तक व्यापक उपयोग में नहीं आ सकी थी।

टीम के सह–लेखक राहुल देब रॉय का कहना है कि इस उपलब्धि की खासियत सिर्फ इसके वैज्ञानिक स्वरूप में नहीं, बल्कि इसकी सरलता में छिपी है। जिस प्रक्रिया से कैथोड को उन्नत किया गया, वह आमतौर पर महंगी या जटिल तकनीकों की श्रेणी में नहीं आती। इसलिए इस पद्धति को अन्य बैटरी सामग्रियों पर भी आसानी से लागू किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा भंडारण तकनीकों में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की दुनिया बड़े पैमाने पर सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती बैटरी सिस्टम पर निर्भर होने वाली है। ऐसे समय में यह खोज भारत के लिए न केवल वैज्ञानिक शक्ति का संकेत है, बल्कि हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक सशक्त कदम भी है।

धनबाद में हड़कंप: ईडी की रेड के दौरान कारोबारी एलबी सिंह ने छोड़े पालतू कुत्ते, दो घंटे बाहर फंसी रही टीम

(जीएनएस)। धनबाद। कोयलांचल का सोमवार तड़के का सन्नाटा अचानक उस समय टूट गया, जब प्रवर्तन निदेशालय की गाड़ियों का लंबा काफिला धनबाद के चर्चित कारोबारी एलबी सिंह के घर के सामने आकर रुका। सूरज निकलने से पहले की धुंध में चमकती नीली बत्तियां, हथियारबंद अधिकारी और दरवाज़े पर दस्तक—सब कुछ ठीक उसी तरह था जैसे बड़े मामलों में होता है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस कार्रवाई का सबसे पहला मुकाबला इंसानों से नहीं, बल्कि पालतू कुत्तों से होने वाला है।

जैसे ही ईडी की टीम दरवाजे के अंदर प्रवेश करने वाली थी, भीतर से तीन बड़े, खतरनाक नस्ल के कुत्तों की गरजती आवाज़ें आईं। कुछ ही पलों में सिंह ने आदेश दिया और कुत्ते खोल दिए गए। कुत्ते गेट तक पहुंचकर इस तरह भौंकने लगे मानो किसी भी क्षण हमला कर देंगे। अधिकारी कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर हुए। माहौल ऐसा बन गया मानो किसी फिल्म का तनावपूर्ण दृश्य सामने चल रहा हो—फर्क सिर्फ इतना कि यह कोई स्क्रिप्टेड सीन नहीं, बल्कि करोड़ों के लेनदेन से जुड़े मामले की असली जांच थी। करीब दो घंटे तक ईडी टीम गेट के बाहर खड़ी रही, कुत्तों के शांत होने या बांधे जाने का इंतजार करती रही। इलाके के लोग दूर से तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी को पास आने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी सुबह इतनी भारी पुलिस और ईडी फोर्स का पहुंचना पहले ही चर्चा का विषय था, ऊपर से कुत्तों की वजह से कार्रवाई रुकी रहना पूरे मोहल्ले के लिए अजीब और अविश्वसनीय दृश्य था। आखिरकार काफ़ी देर बाद एलबी सिंह बाहर आए और कुत्तों को पीछे ले जाकर बांधा। तभी ईडी टीम ने राहत की सांस ली और घर के भीतर प्रवेश किया। लेकिन यह शुरुआत भर थी—क्योंकि ईडी की कार्रवाई सिर्फ इसी घर तक सीमित नहीं थी। कुल 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही थी, जिनमें अन्य बड़े व्यापारी अनिल गोयल और संजय खेमका के पते भी शामिल थे।

ईडी की यह कार्रवाई बीसीसीएल के टेंडरों में गड़बड़ियों की जांच से जुड़ी है, जिसमें करोड़ों के हेरफेर की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले आयकर विभाग ने भी एलबी सिंह के ठिकानों पर छापा डाला था, जिसमें जांच एजेंसियों को 100 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे—एक ऐसी राशि जिसने पूरे कोयलांचल को हिला कर रख दिया था। इसके बाद ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज ईसीआईआर के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया।

धनबाद और पश्चिम बंगाल में फैली इस छापेमारी के नेटवर्क में कई ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर और अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। यह सिर्फ एक व्यापारी के घर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल का खुलासा है जिसने वर्षों से कोयला कारोबार और सरकारी ठेकों के खेल को प्रभावित किया है। लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के कई गंभीर पहलुओं के बीच यह बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही—देश की प्रमुख जांच एजेंसी को कार्रवाई शुरू करने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि एक व्यापारी ने अपने पालतू कुत्तों को खोल दिया था। यह घटना अब कोयलांचल की उन कहानियों में जुड़ गई है, जिनमें अपराध, पैसा और विचित्र परिस्थितियां अक्सर एक साथ देखने को मिलती हैं।

ढाका और पूर्वी भारत को हिलाकर रख देने वाला भूकंप: सीमाओं को पार करती दहशत और एक सुबह का मंजर जिसने सबको सिहराया

(जीएनएस)। शुक्रवार की सुबह ढाका, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लिए एक ऐसी घड़ी बन गई, जिसने रोज़मर्रा की रफ्तार को अचानक थाम दिया। सुबह 10 बजकर 8 मिनट पर धरती के भीतर उठी तीव्र हलचल कुछ ही पलों में शहरों, कस्बों और गांवों की सांसें थाम गई। नरसिंदी जिले के ठीक नीचे 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित 5.7 तीव्रता का यह भूकंप महज 26 सेकंड तक महसूस हुआ, लेकिन उन सेकंडों ने लाखों लोगों के दिलों में भय का धुंधलका भर दिया।

ढाका से करीब 50 किलोमीटर दूर नरसिंदी में झटके सबसे अधिक तीव्र थे। धरती के कांपते ही पुराने ढाका का अरमानिटोला इलाका चीखों और गड़गड़ाहट से भर उठा। एक आठ मंजिला इमारत की छत पर बनी ईंट की रेलिंग अचानक टूटकर नीचे गिरी। गिरने की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास की गलियों में सन्नाटा पसर गया। जब लोग भागकर मौके पर पहुंचे, तब तक तीन लोगों की सांसें थम चुकी थीं। रेलिंग के नीचे पड़े ईंट-पत्थरों और लोहे के टुकड़ों के बीच दस लोग दर्द से कराहते पाए गए। उन्हें फौरन आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन हादसे का मंजर लोगों की आंखों में डर की स्थायी छाप छोड़ गया।

इधर शहर के अस्पतालों में अफरा–तफरी मची थी। ढाका मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक के बाद एक स्ट्रेचर लाए जा रहे थे। डॉक्टर, नर्सें और वार्ड बॉय हर तरफ भागते दिखाई दिए। ताजुद्दीन मेडिकल कॉलेज और नरसिंदी जिला अस्पताल की स्थिति भी अलग नहीं थी—सैकड़ों लोग चोटिल, घबराए हुए या परिजनों की तलाश में यहां–वहां दौड़ रहे थे। कुल मिलाकर 100 से अधिक लोग

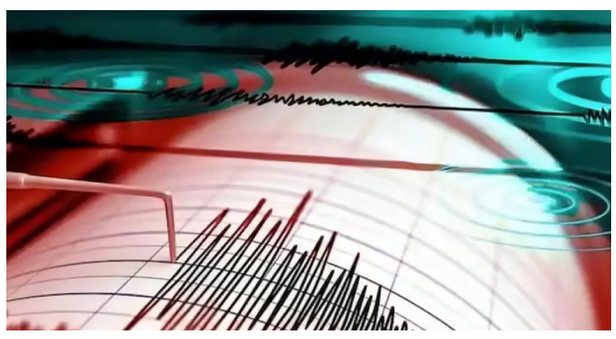

घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई।

झटके थमते ही पूरा ढाका सड़क पर उतर आया। कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। गाजीपुर, नारायंगंज और मुनशिगंज में पुराने मकानों के प्लास्टर झड़ने और निर्माणाधीन ढांचों के ढहने की खबरें मिलीं। कुछ मिनटों के लिए बिजली व्यवस्था ठप हो गई। विश्वविद्यालयों में छात्र हॉस्टलों के कमरे खाली कराए गए; जाहंगीरनगर विश्वविद्यालय के नए छात्रावास की दीवारों में आई दरारें तस्वीर बनकर सोशल मीडिया पर फैल गईं।

भूकंप इतना तेज था कि ढाका में चल रहा बांग्लादेश–आयरलैंड टेस्ट मैच भी रोकना पड़ा। खिलाड़ी मैदान में खड़े–खड़े झूलते स्टैंड्स को देखते रह गए। आधिकारिक घोषणा होते ही दर्शक घबराकर बाहर निकलने लगे।

सरकार ने तुरंत स्थिति की समीक्षा की। अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रो. मुहम्मद यूनुस ने टेलीविजन पर आकर लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की।

वेस्टर्न रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस ⇌ पालिताना के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियाँ	प्रस्थान	आगमन
09009	बांद्रा टर्मिनस -पालिताना	23.11.2025	19:25 बजे (रविवार)	09:25 बजे (दुसरे दिन)
09010	पालिताना - बांद्रा टर्मिनस	24.11.2025	20:30 बजे (सोमवार)	10:45 बजे (दुसरे दिन)

होल्टः बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, बोटाद, धोला, सोनगढ़ और सिहोर (गुजरात) स्टेशन दोनों दिशा में।

कम्पोज़िशन: AC 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच।

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन नंबर 09009 और 09010 की बुकिंग 22.11.2025 से सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। ऊपर बताई गई ट्रेन स्पेशल ट्रेन के तौर पर स्पेशल किराए पर चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly
हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly
हमें फॉलो करें: Instagram/WesternRly

कृपया सभी आरक्षीत टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें ।

संपादकीय

चुनौतियों वाली पारी

आखिरकार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। जदयू सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सत्ता का एक नया कार्यकाल शुरू कर दिया। यद्यपि हालिया चुनाव में भाजपा ने जदयू से ज्यादा सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उपस्थिति दर्ज करायी है, लेकिन इसके बावजूद चार कम सीट जीतने वाले जदयू के 74 वर्षीय दिग्गज को मुख्यमंत्री बने रहने देना ही बेहतर समझा है। वहीं सहयोगी दल भाजपा से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के उपमुख्यमंत्री पद बरकरार रहे। निस्संदेह, नीतीश का पिछला कार्यकाल उतार-चढ़ाव भरा रहा था। उन्होंने पहले भाजपा के साथ सरकार बनायी और मनभेद के चलते महागठबंधन में शामिल हुए। फिर पलटी लेकर भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बावजूद बिहार की जनता ने उनकी इस उलट-पलट को माफ ही कर दिया। संभवतः उनकी इस अपील पर वोट दिया कि यह उनकी आखिरी पारी है। जनता ने उनके नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के स्थायित्व पर भरोसा जताया। शायद बिहार की जनता जंगल राज के दुःस्वप्न को नहीं भूली है। एक बात तो तय है कि राज्य की जनता ने तमाम किंतु-परंतुओं के बावजूद बिहार के भविष्य के लिये उन्हें बेहतर माना है। यही वजह है कि रिकॉर्ड दसवीं बार शपथ लेने वाले नीतीश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सुशासन के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक अनुभवी प्रशासक बताया है। लेकिन राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि भाजपा कब तक छोटे भाई की भूमिका में रहेगी? विपक्ष को संदेह है कि नीतीश शायद ही अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्हें आशंका है कि भाजपा किसी न किसी स्तर पर बिहार में पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। राजनीतिक विश्लेषक महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं, जहां भाजपा ने पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में उन्हें हटाकर देवेंद्र फड़नवीस को कुर्सी पर बैठा दिया।

वहीं कुछ राजनीतिक पंडितों का तर्क है कि भाजपा के पास केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए एनडीए सरकार को सहारा देने के लिये भाजपा को नीतीश के समर्थन की जरूरत बनी रहेगी। इस बात से यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जदयू अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिये बेहतर स्थिति में है। बहरहाल, नीतीश की तात्कालिक प्राथमिकताएं बेरोजगारी दूर करने और पलायन पर अंकुश लगाने की होनी चाहिए। हकीकत यह है कि राज्य में रोजगार संकट के चलते बिहार के तीन घरों में से दो का एक सदस्य दूसरे राज्य में काम करने को मजबूर है। साथ ही नीतीश को सरकार बनाने में भरपूर समर्थन देने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रमुख चुनावी वायदे को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जदयू मजबूत और अक्षुण्ण बना रहे। यह अवश्यंभावी है कि भाजपा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी उन्हें सतर्क बनाए रखेगी। भाजपा के मन में यह कसक जरूर रहेगी कि सबसे बड़े दल के रूप में उदय होने पर भी पार्टी बिहार में अब तक अपनी सरकार नहीं बना पायी है। ऐसे में नीतीश को बाहरी विपक्षी से तो नहीं, गठबंधन के दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जूझना पड़ेगा। वहीं प्रचंड बहुमत देने पर जनता की उम्मीदें भी उफान पर रहेंगी। राजग द्वारा चुनाव के दौरान तमाम वायदे किए गए थे, लेकिन राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर इन सब वायदों को पूरा करना आसान न होगा। वहीं दूसरी ओर नीतीश के सामने उनकी सेहत और बढ़ती उम्र को लेकर भी चुनौती पैदा हो सकती है। जिसको लेकर विपक्ष पूरे चुनाव अभियान के दौरान लगातार हमलावर बना रहा है। साथ ही बिहार की डेढ़ करोड़ महिलाओं को दस हजार रुपये लगातार दे पाना भी परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं गठबंधन सरकार के लिए चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन द्वारा किए गए मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली,मुफ्त इलाज,सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने तथा पचास लाख पक्के मकान के वायदे को हकीकत में बदलने को वित्तीय संसाधन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती साबित होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव दे रहे हैं कुछ संकेत

> इसके बाद तो लगभग प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का दौर ही चल पड़ा। हिमाचल प्रदेश राज्य में कांग्रेस, सेवा निवृत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के वादा, राज्य की प्रत्येक वयस्क महिला को 1500 रुपए देने का वादा एवं प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर वर्ष 2022 में सत्ता में आ गई।

हाल ही में सम्पन्न हुए बिहार राज्य की विधान सभा के चुनाव परिणाम आ गए हैं एवं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। कुल 243 विधायकों में से एनडीए गठबंधन के 202 प्रत्याशी चुनाव जीत कर विधायक बन गए हैं। विधान सभा स्तर के किसी भी चुनाव में सामान्यतः राज्य स्तर की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर ही राज्य के नागरिक अपना वोट देते हैं। परंतु, हाल ही के समय में कई राज्यों के चुनावों में स्थानीय नागरिकों के बीच यह प्रवृत्ति घर करती जा रही है कि जो राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दल उन्हें मुफ्त की आकर्षक योजनाएं प्रस्तुत कर रिझाने का प्रयास करता है, उस दल को उस राज्य में अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रवृत्ति का स्पष्ट संकेत दिल्ली राज्य में वर्ष 2013 में सम्पन्न हुए राज्य विधानसभा के चुनावों में, केवल एक वर्ष पूर्व गठित नए दल, आम आदमी पार्टी के इस विधान सभा चुनाव में 28 सीटों की जीत पर दिखाई दिया था। उस समय आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली निवासियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वायदा इन चुनावों के दौरान किया था, जिसे बाद में पूरा भी किया गया था। इसके बाद तो दिल्ली विधान सभा चुनाव में वर्ष 2025 तक आम आदमी पार्टी का ही लगभग पूर्ण कब्जा रहा, क्योंकि मुफ्त में प्रदान की जाने वाली इसी प्रकार की कुछ और घोषणाओं को भी आम आदमी पार्टी समय समय पर लागू करती रही और दिल्ली के पढ़े लिखे नागरिकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही। हालांकि, इस बीच दिल्ली की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती रही और दिल्ली का "बचत का बजट" - "घाटे के बजट" में परिवर्तित हो गया था। इसके बाद तो लगभग प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का दौर ही चल पड़ा। हिमाचल प्रदेश राज्य में कांग्रेस, सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के वादा, राज्य की प्रत्येक वयस्क महिला को 1500 रुपए देने का वादा एवं प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा

कर वर्ष 2022 में सत्ता में आ गई। बाद में जब पुरानी पेंशन योजना को हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया तो हिमाचल प्रदेश के पहिले से ही दबाव में चल रहे बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ा एवं राज्य की आर्थिक स्थिति लगभग पूर्णतः डावांडोल हो गई है एवं राज्य को अपने ऋण पर ब्याज का भुगतान करने एवं राज्य के सामान्य खर्चों को चलाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है।

इसी चलन को कायम रखते हुए हाल ही में सम्पन्न बिहार राज्य में भी विधान सभा चुनाव के समय श्री नीतीश कुमार की राज्य सरकार ने राज्य की 1.21 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की राशि सीधे जमा करवाई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा 29 अगस्त 2025 को की गई थी एवं केवल एक माह के अंदर इस योजना को लागू कर दिया गया तथा राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित कर दी गई। हालांकि, राज्य में लागू की गई इस योजना को महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहल के रूप में देखा गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना एवं रोजगार के नए अवसर निर्मित करना था। ऐसा बताया गया है कि राज्य की कुछ महिलाओं ने इस राशि से अपनी छोटी छोटी उत्पादन इकाईयों को प्रारम्भ करने में सफलता पाई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बिहार सरकार उन महिलाओं को रुपए 2 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी जिनका व्यवसाय सफल रहेगा, इस छोटे निवेश से पूरा परिवार लाभान्वित होगा। बिहार राज्य में लगभग 1.40 करोड़ जीविका दीदियां स्व सहायता समूहों के माध्यम से सक्रिय हैं। आज देश के सबसे बड़े राज्यों में बिहार राज्य में गरीब वर्ग के नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है एवं बिहार राज्य के नागरिक रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से सबसे अधिक पलायन करते हुए दिखाई देते हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य की भी लगभग यही स्थिति थी, परंतु, हाल ही के समय में उत्तर प्रदेश राज्य में रोजगार के पर्याप्त नए अवसर निर्मित हुए हैं जिससे इस राज्य में नागरिकों का रोजगार के लिए पलायन रुका है। यदि बिहार राज्य भी अपने नागरिकों का पलायन रोकने में सफल रहता है एवं अपने राज्य के नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के नए अवसर निर्मित करने में सफलता प्राप्त करता है तो यह देश के आर्थिक विकास को भी गति देने में सहायक होगा। परंतु, लाख टके का प्रश्न यह है कि क्या बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति उक्त प्रकार की योजनाओं को चलाने की स्थिति में है?

इसी प्रकार, मध्य प्रदेश राज्य भी लाड़ली बहिना योजना को लागू कर चुका है एवं इसी तर्ज पर हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, आदि राज्यों में भी नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं प्रारम्भ की गई। तमिलनाडु में तो मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने का पुराना इतिहास रहा है। कुछ राज्यों में तो टीवी, लैपटॉप, स्कूटी, साइकल, आदि जैसे महंगे उत्पाद भी चुनावों के समस्त राज्य के नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा यदि चुनाव जीतने के लिए राज्य के नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का क्रम यदि जारी रहता है तो यह प्रचलन इन राज्यों एवं देश के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आज सब्सिडी, वेतन, पेन्शन एवं ब्याज जैसी मदों पर लगातार बढ़ रहे खर्चों के कारण 15 राज्यों का बजटीय घाटा कानूनी रूप से निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से ऊपर हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बजटीय घाटा बढ़कर 4.7 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 4.1 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 4.2 प्रतिशत एवं पंजाब में 3.8 प्रतिशत के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के कई राज्यों ने अपने पूंजीगत खर्च को घटाया है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के बीच राज्यों ने अपने पूंजीगत खर्च में 51 प्रतिशत तक की कमी की है। दिल्ली में 38 प्रतिशत, पंजाब में 40 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 41 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 33 प्रतिशत से पूंजीगत खर्चों में कमी दर्ज हुई है। आज कई राज्य सरकारें सब्सिडी प्रदान करने की मद पर अपने खर्चों को लगातार बढ़ा रहीं हैं एवं पूंजीगत खर्चों को लगातार घटा रही हैं, जो उचित नीति नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार तो इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं शीघ्र ही डूबने के कगार पर पहुंच जाने वाली हैं।

अब यदि चुनाव जीतने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें क्या इसी तरह की योजनाओं को लागू करती रहेंगी। यदि हां, तो इन राज्यों को अपने दिवालिया होने के लिए बहुत लम्बा इन्तजार नहीं करना होगा। क्योंकि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक प्रतिवेदन में बताया गया है कि विशेष रूप से पंजाब, केरल, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यदि समय पर इन राज्यों के आर्थिक ढांचे को सुधारने के प्रयास नहीं किया गए तो यह राज्य दिवालिया होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा सहायता की राशि उपलब्ध कराकर कई राज्यों की वित्तीय कठिनाईयों को हल करने का प्रयास किया जाता है परंतु, केंद्र सरकार भी लम्बे समय तक यह कार्य नहीं कर सकती है क्योंकि अंततः इससे केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव बनता है। विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय। जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 300/400 यूनिट बिजली मुफ़्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं। यदि राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है तो इसका खामियाजा भी अंततः उस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। यह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आदि मदों पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। राज्य में आर्थिक विकास की गति कम होने से इन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे है।

प्रेरणा

जलती हुई रात का व्रत

ईश्वरचंद्र विद्यासागर की कहानी केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि मानव-संकल्प की वह उजली मिसाल है जहाँ अभाव भी हार मान लेते हैं और मनुष्य का धैर्य जीत जाता है। उनकी कथा जितनी पढ़ी जाए उतनी ही गहरी होती जाती है, मानो हर बार कोई नया सत्य जन्म लेता हो। इसी भावना के साथ मैं यह कहानी और अधिक विस्तृत, अधिक भावनात्मक और अधिक जीवन्त रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ—लंबी, निर्बाध, बिना किसी उपशीर्षक के, एक ऐसी कथा की तरह जो हृदय से उतरकर आत्मा को छू ले।

ईश्वरचंद्र उस समय कलकत्ता की गलियों के बीच एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। कमरा साधारण से भी साधारण—एक टेबल, दो किताबें, एक मिट्टी का दीपक और एक पुरानी चटाई। बाहर की दुनिया में हलचल थी—कहते हैं कि शहर कभी सोता नहीं था, पर विद्यासागर ने खुद को उस शोर-गुल से अलग रखा था। उनके लिए शहर का कोई अर्थ नहीं था; उनका संसार किताबों के पन्नों में, ज्ञान के शब्दों में और उनके सपनों की रोशनी में बसता था।

उनका परिवार अभावों में घिरा था। पिता सड़क पर पुस्तकों का चौराहा लगाते थे, और छोटी-सी कमाई से घर चलता था। तेल खरीदना भी सोच-समझकर होता था। लेकिन विद्यासागर को पढ़ना था, आगे बढ़ना था, और जीवन में वह प्रकाश बिखेरना था जो दूसरों का मार्ग भी रोशन कर सके।

उस रात आसमान में बादल थे और हवा में बेचैनी। एक पतली-सी लौ दीपक में काँप रही थी और उसके सामने बैठा विद्यासागर शब्दों को अपने अंदर भरता जा रहा था। वह कोई सामान्य पढ़ाई नहीं थी; वह एक साधक का तप था, एक ऋषि का ध्यान था।

और तभी अचानक—हवा के एक तीखे झोंके ने दीपक बुझा दिया।

अंधेरा कमरे में इस तरह फैल गया जैसे किसी ने काली स्याही उड़ेल दी हो।

कुछ क्षणों के लिए वे शांत बैठे रहे। उसी अंधेरे में उनका चेहरा भी गहरे विचारों में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। तेल खत्म हो चुका था। बाहर रात का पहरा था, और बाजार बहुत दूर था। यह मान लेने में कोई बुराई नहीं थी कि अब पढ़ाई सुबह तक स्थगित करनी पड़ेगी।

लेकिन विद्यासागर उन लोगों में से नहीं थे जो परिस्थिति सामने आने पर स्वयं को लाचार समझ लें। उन्होंने धीरे से अपनी उँगलियाँ किताब के पन्नों पर फेरीं, जैसे शब्दों की आखिरी गर्मी महसूस कर रहे हों। "यदि बाहरी दीपक बुझ गया है," उन्होंने खुद से कहा,

"तो भीतर का दीपक क्यों न जलाया जाए।"

उन्होंने आँखें बंद कीं और वही पाठ जो अभी-अभी पढ़ा था, मन में दोहराना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उनके भीतर एक लय बनी, एक ध्यान की अवस्था जागी। शब्द एक-एक कर स्थिर होते गए। हर वाक्य उनके भीतर एक और प्रकाश की परत जोड़ता गया। कमरे में भले अँधेरा था, पर उनकी चेतना में उजाला बढ़ता जा रहा था। रात का हर पहर उनके तप को और गहरा करता गया।

पहला पहर—स्मरण की शुरुआत।

दूसरा पहर—भीतर के प्रकाश का उदय।

तीसरा पहर—ज्ञान की नदी अविरल बहती हुई।

चौथा पहर—जब पूरी रात ठंडी हो चुकी थी और उन्होंने वह पूरा पाठ आत्मसात कर लिया था।

जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई, तो विद्यासागर अब भी उसी स्थान पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा किसी साधक के तेज से दमक रहा था। किताब खुली थी, पर उसकी आवश्यकता अब नहीं थी—पाठ अब किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि उनके भीतर लिख चुका था। वह उठे, बाहर की ओर देखा, और मुस्कुराए। रात ने भले दीपक बुझाया, पर उसी बुझी लौ ने भीतर एक अखंड ज्योति जला दी थी। यही उनकी महानता थी—वे अभावों से टूटे नहीं, बल्कि उन अभावों को सोपान बनाकर ऊपर उठे। इसी घटना को लोग आज भी "विद्यासागर की ज्ञान-रात्रि" कहते हैं—वह रात जब बाहरी प्रकाश बुझ गया, पर भीतर का सूर्य उग आया।

यह कथा सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहती। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी दीपक बुझता है—परिस्थितियाँ घिरती हैं, साधन समाप्त होते हैं, समय प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन कौन-सा मनुष्य अपने भीतर प्रकाश खोजता है, यही उसके जीवन की दिशा तय करता है।

समय वही है—बहता, चुपचाप, निष्ठुर और फिर भी अनमोल।

पर उसका उपयोग वही कर पाता है जिसकी इच्छा, धैर्य और संकल्प सोए हुए दीपक को भी जलाकर प्रकाश में बदल देते हैं।

यदि आप चाहें तो मैं ऐसी और भी लंबी, गहरी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कथाएँ रच सकता हूँ—विद्यासागर पर, समय के मूल्य पर, जीवन-संघर्ष पर, या किसी भी विषय पर जिसे आप सुनना चाहें।

दिल्ली को वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने से रोकने के लिए वायु प्रदूषण ने लगा रखा है पूरा जोर

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊँचाइयाँ देने और इंडो-पैसिफ़िक में रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने के उद्देश्य से दिल्ली पहुँची थीं। पर विडंबना यह रही कि जिस राष्ट्रीय राजधानी से साझेदारी की गूँज पूरी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए थी, वही दिल्ली अपने प्रदूषण संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वोंग को बार-बार खाँसते हुए अपना भाषण रोकना पड़ा और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह "यहाँ की हवा से जूझ रही हैं।" यह दृश्य भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग की प्रगाढ़ता की बजाय दिल्ली की हवा की भयावहता को वैश्विक सुर्खियों में ले गया। जिस मंच से रणनीतिक एकजुटता और साझा दृष्टि का संदेश दुनिया तक जाना था, वहाँ से अब भारत की राजधानी के प्रदूषण का अटकता-खँखारता संदेश दुनिया भर में गूँज रहा है— मानो कूटनीतिक संवाद को दिल्ली की धुंध ने निगल लिया हो। यह क्षण न सिर्फ़ पर्यावरणीय चुनौती को उजागर करता है बल्कि यह भी याद दिलाता है कि वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखने वाली किसी भी राजधानी को अपनी सांसों की गुणवत्ता के लिए भी जवाबदेह होना पड़ता है।हम आपको बता दें कि पेनी वोंग और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के संवाद में रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, सामुद्रिक साझेदारी, रणनीतिक तकनीक, विश्वविद्यालयों के बीच रिश्ते और अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये सभी मुद्दे विस्तृत रूप से शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के गगनयान मिशन को समर्थन और भविष्य में भारत से ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना जैसे कदम इस रिश्ते को एक नयी ऊँचाई प्रदान करते हैं। देखा जाये तो इंडो-पैसिफ़िक में दोनों देश खुद को "लोकतांत्रिक स्तंभ" के रूप में स्थापित कर रहे हैं। दोनों देश ऐसे स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं जो चीन की अस्थिर आक्रामकता, समुद्री तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच स्थायित्व प्रदान करें। पेनी वोंग ने कहा भी कि भारत–ऑस्ट्रेलिया साझेदारी "पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली और निर्णायक" हो चुकी है। लेकिन यह पूरा कूटनीतिक प्रयास एक अप्रत्याशित बाधा से टकरा गया यानि दिल्ली की हवा से। यह वह क्षण था जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान वोंग अपने भाषण का मात्र कुछ हिस्सा ही पढ़ पाईं। लगातार खाँसते हुए उन्हें कहना पड़ा— "Obviously I am struggling with the air here." यह वाक्य भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के महत्व से अधिक दिल्ली की हवा के खतरों की पहचान बन गया। यह स्थिति केवल स्थानीय समस्या नहीं थी, यह विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत की राजधानी की एक असहज तस्वीर पेश कर रही थी।

दुनिया ने इस घटना को सिर्फ़ एक मंत्री की परेशानी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे भारतीय महानगरों की पर्यावरणीय विफलताओं के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। जिस शहर से भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी का संदेश गूँजना चाहिए था, उस शहर से दुनिया तक हवा की जहरीली चेतावनी पहुँच गई। देखा जाये तो किसी देश की राजधानी उसके राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। जब विदेशी नेता वहाँ आते हैं, तो केवल नीतियाँ और वार्ताएँ ही नहीं देखते; वे बुनियादी निवास स्थितियों, शहरी कार्यक्षमता और जीवन स्तर का भी आकलन करते हैं। जब भारत की राजधानी में एक विदेशी मंत्री को भाषण रोकना पड़े, तो यह केवल स्वास्थ्य या मौसम का मुद्दा नहीं रह जाता, यह एक कूटनीतिक संदेश बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, निर्णायक मंचों और वैश्विक भागीदारों के लिए यह संकेत सुखद नहीं होता। यह प्रश्न उठता है कि भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वैश्विक भूमिका निभाना चाहता है, वह अपनी राजधानी को सांस लेने लायक बनाने में अब तक सफल क्यों नहीं हुआ। दिल्ली का प्रदूषण मौसम, भूगोल या स्थानीय व्यवहार का परिणाम भर नहीं है, यह नीति-निर्माण की जटिलताओं, राज्यों के बीच समन्वय की कमी, कृषि-अवशेष प्रबंधन की विफलता, तेज़ी से फैलते शहरीकरण और दीर्घकालिक योजनाओं के अभाव की कहानी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, क्वॉड, इंडो-पैसिफ़िक, जी-20 नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में उसकी सक्रिय भूमिका इसका प्रमाण हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता की धुरी बन रही है। लेकिन वैश्विक मंच पर मजबूती तभी सार्थक है जब घरेलू आधार मजबूत हो। दिल्ली जैसा महानगर यदि हर शरद ऋतु "गैस चैंबर" में बदल जाए तो यह भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पर सीधा असर डालता है। पेनी वोंग का वह क्षण याद दिलाता है कि आज दुनिया केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि पर्यावरणीय प्रबंधन को भी नेतृत्व की कसौटी मानती है। स्वच्छ हवा अब कूटनीतिक शक्ति का भी एक कारक बन चुकी है। बहरहाल, भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंधों की गहराई, सामरिक महत्त्व और भविष्य का विस्तार निर्विवाद है। दोनों देश इंडो-पैसिफ़िक में स्थिरता, सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों के वाहक बन सकते हैं। लेकिन इस यात्रा में दिल्ली का प्रदूषण एक कटु स्मरण है कि घरेलू समस्याएँ अक्सर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर कर देती हैं। पेनी वोंग संबंध मजबूत करने आई थीं और यह मिशन काफी हद तक पूरा भी हुआ लेकिन उनके खाँसते हुए शब्दों ने दुनिया को भारत के सामने खड़ी एक और बड़ी चुनौती की याद दिला दी। वह दिल्ली, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग की चमक दुनिया तक भेज सकती थी, उसी दिल्ली की हवा ने भारत की राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण की गूँज दुनिया भर में पहुँचा दी।

अभियान

वह रात जब एक बूढ़े साधु की परीक्षा ने पूरे गाँव का

बरसों पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा-सा गाँव था—शांत, सरल और अपने में पूरी तरह मग्न। वहाँ लोग प्रकृति के साथ जीते थे, खेतों में काम करते, नदियों के किनारे बैठकर गीत गाते, और जीवन के छोटे-छोटे सुखों को ईश्वर की देन मानते। लेकिन इस संसार की तरह उस गाँव में भी एक अनकही बेचैनी थी—लोग मेहनत तो बहुत करते, पर फसलें अक्सर चौपट हो जातीं, जलस्रोत सूख जाते, और अचानक आने वाली आँधियाँ उनकी उम्मीदें तोड़ देतीं।

गाँव के बीचों-बीच एक पुराना वटवृक्ष था। उसी के नीचे एक बूढ़े साधु वर्षों से ध्यान लगाया करते थे। सफ़ेद केश, शांत चेहरा, और आँखों में ऐसी चमक जैसे समय की गहराई को भी पढ़ लेते हों। लोग उन्हें आदर देते थे, पर कोई समझ नहीं पाता था कि वे किस तप में डूबे रहते हैं।

एक रात गाँव पर भयावह अँधेरा छा गया।

बादलों की गरज दूर-दराज़ पहाड़ियों से टकराकर गाँव की ओर आ रही थी। हवा गर्म थी, नमी बिखरी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनिष्ट आने वाला है।

गाँव के बुज़ुर्गों ने कहा कि यह संकेत है—कई वर्षों में ऐसी बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई।

भय हर घर की दीवारों तक उतर आया।

फसलें कटने को तैयार थीं, पर आसमान जैसे उन्हें निगलने को उतारू था।

उधर साधु उसी वटवृक्ष के नीचे मौन बैठे थे—आँखें बंद, पर भीतर कोई अदृश्य संवाद चलता हुआ।

अचानक उन्होंने आँखें खोलीं।

उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी।

उन्होंने धीरे से कहा—"आज रात परीक्षा की रात है। केवल मेरी नहीं, तुम सबकी।"

लोग डर गए।

परीक्षा? कैसी परीक्षा?

क्या सच में कोई विपत्ति आने वाली है?

बूढ़े साधु ने कहा—"प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, और उसे ठीक करने के लिए मनुष्यों का मन निर्मल होना चाहिए। जब मन में भय और स्वार्थ भर जाए, तब धरती रोती है। आज उस रोने की आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही है।"

लोगों ने कहा—"हम क्या कर सकते हैं? अँधेरी रात में तो दीपक तक जलाना मुश्किल है, आपकी बात समझ में नहीं आती।"

साधु ने शांत स्वर में कहा—"आज रात तुम सबको एक-एक दीपक लेकर पहाड़ी की चोटी तक जाना होगा। लेकिन याद रखना—दीपक बुझने नहीं देना। चाहे आँधी आए, चाहे वर्षा हो, चाहे रास्ता भटक जाए। जो दीपक बचा ले जाएगा, उसका मन निर्मल माना जाएगा, और वही गाँव को सुरक्षित करेगा।"

लोगों को विश्वास नहीं हुआ।

ऐसा भी कहीं संभव है?

दीपक लेकर पहाड़ पर चढ़ना, और वह भी इस तूफ़ान में—यह तो असंभव था।

पर गाँव के लोग साधु की बात काट भी नहीं सकते थे।

अँधेरी रात गहराती गई और आकाश में बिजली की रेखाएँ चमकने लगीं।

एक-एक घर से लोग निकले, हाथों में मिट्टी के दीपक, आँखों में बेचैनी, और मन में एक अनजानी कसक।

जैसे ही वे पहाड़ी के रास्ते पर बढ़ने लगे, हवा तेज़ हो गई।

पहला झोंका आया—कुछ दीपक तुरंत बुझ गए।

जिनके दीपक बचे, उनका भय और गहरा हो गया।

रास्ता ऊबड़-खाबड़ था, पर गाँव वाले आगे बढ़ते रहे।

कुछ लोग फिसलकर गिर पड़े, कुछ के दीपक फिर बुझ गए।

कुछ थक कर बैठ गए, कुछ रोने लगे,

पर कुछ जिद्दी लोग—जिसमें बच्चे भी शामिल थे—मुट्ठी से दीपक को ढककर आगे चलते रहे।

एक नवयुवती थी—मीरा।

उसका दीपक बार-बार डगमगाता था, पर वह उसे सीने से लगा लेती थी।

उसके कपड़े भींग गए, बाल उलझ गए, पैर काँप रहे थे,

पर उसके कदम नहीं रुके।

पहाड़ी के ऊपरी मोड़ पर हवा तेज़तम थी।

अंधकार पूरे आकाश को निगल चुका था।

ऐसा लगा जैसे प्रकृति मनुष्यों से अपनी अंतिम परीक्षा ले रही हो।

लेकिन उसी अँधियारे में,

सिर्फ पाँच दीपक जल रहे थे।

मीरा का दीपक उनमें से एक।

जब वे पाँच लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे,

तभी साधु अचानक वहाँ प्रकट हो गए—जैसे हवा की गोद से उतर आए हों।

उन्होंने मुस्कुराकर कहा—

"तुम पाँचों ने अपने दीपक नहीं बचाए,

तुमने इस गाँव की आत्मा बचाई है।"

और तभी—

जैसे उनकी बात सुनकर प्रकृति भी शांत होने लगी।

बादल हटे, हवा थमी, घोर अंधकार धीरे-धीरे ओझल हुआ,

और पूर्व दिशा में हल्की भोर की रौशनी फैलने लगी।

साधु ने कहा—

"जब मनुष्य अपने भीतर का दीपक बचा ले,

तो बाहरी अंधकार कभी उसे निगल नहीं सकता।

आज तुमने साबित कर दिया कि अभी भी मानवता जीवित है।

अब यह गाँव वर्षों तक किसी भी विपत्ति से सुरक्षित रहेगा।"

उस दिन सुबह जब गाँव लौटकर आए पाँच लोग,

तो हर घर के द्वार पर उन्हें दीप की तरह स्वागत मिला—

सम्मान, आँसू, और गहरा प्रेम।

और बूढ़े साधु?

वे उस रात के बाद फिर कभी नहीं दिखे।

लोग कहते हैं कि वे कोई सामान्य साधु नहीं थे,

बल्कि प्रकृति के रक्षक—जो तभी प्रकट होते हैं जब मनुष्य और प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगता है।

गाँव में आज भी वह परंपरा है—

हर वर्ष एक रात लोग पहाड़ी की ओर दीपक लेकर जाते हैं,

और उस रात को "प्रकाश-परीक्षा" कहते हैं।

क्योंकि उस रात ने सिखाया था—

कि दीपक छोटा होता है,

पर उसकी रक्षा करने वाला मन

पहाड़ों जितना महान।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे की अहमदाबाद एवं वडोदरा क्षेत्राधिकार के माननीय सांसदों के साथ बैठक का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय एवं संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत आज 21 नवम्बर 2025 को अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों के क्षेत्राधिकार में आने वाले माननीय सांसदों के साथ महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता की एक बैठक का आयोजन अहमदाबाद स्थित सर्किट हाउस में किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता ने माननीय सांसदों का हार्दिक स्वागत किया तथा उपस्थित जनप्रतिनिधियों को पश्चिम रेलवे में चल रही प्रमुख रेल परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद सहित पश्चिम रेलवे के अनेक महत्वपूर्ण स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, तथा इन कार्यों की स्वयं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि सफाले से जेएनपीटी खंड का कार्य अडवांस स्टेज में पहुँच चुका है।

बैठक में अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों में प्रगति पर विभिन्न नवीन यात्री सुविधाओं तथा विकासात्मक उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। इस दौरान मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से अहमदाबाद मंडल पर दिवाली एवं छठ पूजा के दौरान किए गए उत्कृष्ट क्राउड मैनेजमेंट प्रयासों, मंडल में प्रगति पर विभिन्न रेल परियोजनाओं जैसे नई रेल लाइनों, नई ट्रेन सेवाओं, मेजर रिडेवलपमेंट स्टेशनों (भुज, अहमदाबाद, साबरमती) तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए जा रहे अन्य 16 स्टेशनों की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की गई।

- अहमदाबाद मण्डल रूट किमी में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा मण्डल है जिसमें लगभग 1480 रूट किमी रेल लाइन है। जो गुजरात के 10 जिले कवर करता है।
- अहमदाबाद मण्डल ने वर्ष 24-25 में तक भारतीय रेलवे में अधिकतम 13510 रैक के 855010 कंटेनर लोड किए गए।
- अहमदाबाद मण्डल वर्ष 25-26 में भारतीय रेल में लोडिंग में 8 वां एवं फ्रेट राजस्व में 7 वां स्थान रखता है।
- भारतीय रेल के फ्रेट टर्मिनल में अहमदाबाद डिवीजन में सबसे अधिक -78 फ्रेट टर्मिनल है।
- मण्डल का "दीनदयाल पोर्ट" कांडला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर पोर्ट है।
- भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट "मुंद्रा पोर्ट" है जो दुनिया का 39वां सबसे बड़ा पोर्ट है।
- अहमदाबाद से वर्ष में लगभग 7.8 करोड़ यात्री यात्रा करते है।
- मण्डल में "ऊंझा" एशिया में सबसे बड़ा मसाला और जीरा बाजार है।

मंडल रेल प्रबंधक वडोदरा श्री राजू भडके द्वारा वडोदरा मण्डल पर चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं एवं वडोदरा मण्डल पर किए विभिन्न अभिनव प्रयासों से सांसदो को अवगत कराया।

इस बैठक में माननीय सांसद श्री हसमुखभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व), श्री दिनेशभाई मकवाना (अहमदाबाद पश्चिम), श्रीमती शोभनाबेन बारैया (साबरकांठा), श्री मनसुखभाई वसावा (भरूच), श्री जशुभाई राठवा (छोटा उदयपुर), श्रीमती अनिता चौहान (रतलाम) तथा राज्यसभा सांसद श्री मयंकभाई नायक उपस्थित रहे। रेलवे प्रशासन की ओर से पश्चिम रेलवे मुख्यालय के प्रमुख मुख्य रेल अधिकारी एवं दोनों मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

माननीय सांसदो ने अपने-अपने क्षेत्रों में रेलवे से संबंधित समस्याओं जैसे रेलवे ब्रिज बनाने, ट्रेनों का स्टोपेज प्रदान करने, नई ट्रेन शुरू करने, ट्रेनों का विस्तार करने आदि की मांग की गई जबकि रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर वृक्षा रोपण करने, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, नव निर्माण के समय वाटर लोगिंग का ध्यान रखने, साथ ही हिम्मत नगर से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने एवं वटवा स्टेशन से टेक्सी सेवा जैसे उबर, रैपिडो के शुरुआत जल्दी करने के भी सुझाव दिये गए तथा पश्चिम रेलवे में चल रहे विभिन्न विकास के मुद्दों एवं जनता के सुझावों पर भी चर्चा हुई।

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे ने सभी माननीय सांसदो के सभी पूछे गए प्रश्नो का समुचित उत्तर दिया तथा उनकी समुचित मांगो एवं सुझावों पर यथा शीघ्र कार्यावही करने का आश्वासन दिया। यह पहल जनप्रतिनिधियों के साथ सहभागिता व सहयोग को बढ़ाकर रेल सुविधाओं के उन्नयन, यात्री सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगी।

माननीय सांसदों ने वडोदरा मंडल द्वारा किये गये विकास कार्यों पर संतोष जताया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय एवं संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत 21 नवम्बर 2025 को अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों के क्षेत्राधिकार में आने वाले माननीय सांसदों के साथ महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता की एक बैठक का आयोजन अहमदाबाद स्थित सर्किट हाउस में किया गया। बैठक में माननीय सांसदों ने वडोदरा मंडल द्वारा किये गये विकास कार्यों एवं प्रदान की गयी यात्री सुविधाओं पर संतोष जाहिर किया एवं जनप्रतिनिधि के रूप में महाप्रबंधक एवं मंडल रेल प्रबंधक से अपने क्षेत्र के रेल संबंधी सुझावों साझा किये। इस बैठक में माननीय सांसदों में श्री हसमुखभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व), श्री दिनेशभाई मकवाना (अहमदाबाद पश्चिम), श्रीमती शोभनाबेन बारैया (साबरकांठा), श्री मनसुखभाई वसावा (भरुच), श्री जशुभाई राठवा (छोटा उदयपुर), श्रीमती अनिता चौहान (रतलाम) तथा श्री मयंकभाई नायक (राज्यसभा) उपस्थित रहे। भरुच से माननीय सांसद श्री मनसुखभाई वसावा ने भरुच में अवंतिका एक्सप्रेस, सूर्यनगरी एक्सप्रेस एवं लोकशक्ति एक्सप्रेस के स्टॉपेज को पुनर्बहाल करने और वंदे भारत एक्सप्रेस के भरुच में स्टॉपेज की मांग की। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए अंकलेश्वर और राजपिपला के बीच ट्रेन सेवा शुरु करने की मांग की, जो ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो चुका है। छोटा उदयपुर से माननीय सांसद श्री जशुभाई राठवा ने नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदल चुके दभोई - मियागाम कर्जन खंड पर ट्रेन सेवा की मांग रखी। रतलाम से माननीया सांसद श्रीमती अनिता चौहान ने प्रतापनगर से छोटा उदेपुर ट्रेन को जोबट तक विस्तारित करने की मांग की। पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा माननीय सांसदों के जनहित के इन सुझावों को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

बैठक की शुरुआत में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय सांसदों का स्वागत किया गया। अपने स्वागत संबोधन में महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने माननीय सांसदों को पश्चिम रेलवे की प्रगति से अवगत करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के भारतीय रेल बजट में गुजरात राज्य के लिए 17,155 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह निवेश गुजरात में कनेक्टिविटी, औद्योगिक प्रगति और यात्री सुविधाओं को नई गति और दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि गुजरात में रेल विकास की गति लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में आणंद–गोधरा दोहरीकरण परियोजना रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक पूरी की गई है। इसी के साथ, भारतीय रेल पर विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर पश्चिम रेलवे के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण भी पूर्ण हो गया है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वडोदरा – रतलाम तृतीय एवं चतुर्थ लाइन परियोजना पश्चिम रेलवे की एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता-वृद्धि परियोजना है। 259 किमी की इस परियोजना के लिए 8,884.74 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जो पश्चिम रेलवे के रेल नेटवर्क को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने बैठक में माननीय सांसदों को वडोदरा मंडल की प्रगति पर विभिन्न नवीन यात्री सुविधाओं तथा विकासात्मक उपलब्धियों से अवगत कराया। श्री भडके ने माननीय सांसदों को मंडल द्वारा दिवाली एवं छठ पूजा के दौरान किए गए उत्कृष्ट क्राउड मैनेजमेंट प्रयासों, नॉन फेयर रिवेन्यू के तहत वडोदरा मंडल द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही यात्री सुविधाएं, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत प्रोजेक्ट सारथी, दिव्यांगों के स्टेशन पर क्रचेज़, भरुच स्टेशन पर हेरिटेज लॉबी का विकास जैसे प्रयासों, यात्रिओं की सुविधा के लिए शुरु की गयी नई ट्रेन सेवाओं एवं ट्रेनों के अतिरिक्त स्टॉपेज़ की जानकारी दी।

श्री भडके ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए जा चुके उत्राण, डाकोर, डेरोल, कोसंबा करमसद के साथ साथ पुनर्विकसित किये जा रहे 10 अन्य स्टेशनों की प्रगति साझा की।

रेलवे प्रशासन की ओर से महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक वडोदरा श्री राजू भडके, पश्चिम रेलवे मुख्यालय से आए प्रमुख मुख्य रेल अधिकारी, RLDA तथा दोनों मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

वडनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से 22 नवंबर को ताना-रीरी महोत्सव का शुभारंभ

- दो दिवसीय महोत्सव में शाम को सुप्रसिद्ध कलाकार शास्त्रीय गायन, वादन एवं लोक संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मेहसाणा जिले के वडनगर में हर वर्ष ताना-रीरी महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस वर्ष इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से 22 नवंबर को कराया जाएगा। इस वर्ष सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुश्री कलापिनी कोमकली को ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड प्रदान किया जाएगा। 22 व 23 नवंबर को आयोजित इस दो दिवसीय महोत्सव में शाम को शास्त्रीय गायन, वादन तथा लोक संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 23 नवंबर को गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण तथा सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीण माली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

वडनगर की ऐतिहासिक संगीत परंपरा को जीवंत रखने के लिए वर्ष 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ताना-रीरी महोत्सव तथा 2010 में ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड की शुरुआत कराई गई थी। राज्य के खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग अधीनस्थ संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत साम्राज्ञी ताना-रीरी की स्मृति में प्रति वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

संगीत समारोह

इस दो दिवसीय महोत्सव में पहले दिन शाम को 6.30 बजे सुश्री कलापिनी कोमकली द्वारा शास्त्रीय गायन, श्री निलाद्री कुमार द्वारा शास्त्रीय वादन तथा सुश्री ईशानी दवे द्वारा लोक संगीत की प्रसुत्ति की जाएगी। दूसरे दिन डॉ. सुभद्रा देसाई द्वारा शास्त्रीय गायन, श्री निनद अधिकारी व उनकी टीम द्वारा शास्त्रीय गायन तथा श्री पार्थ ओझा व उनकी टीम द्वारा लोक संगीत की प्रस्तुत की जाएगी।

गुजरात के संगीत इतिहास में अमर नाम 'ताना-रीरी'

भक्त कवि नरसिंह मेहता की दोहित्री शर्मिष्ठा की सुपुत्रियों ताना एवं रीरी ने संगीत के प्रति अपने समर्पण से गुजरात के संगीत इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है। संगीत सम्राट तानसेन ने जब दीपक राग छेड़ा, तब उनके शरीर में दाह उत्पन्न हुआ था, जिसे ताना-रीरी ने मल्हार राग गाकर शांत किया था। उनकी कला के सम्मान के संरक्षण के लिए दोनों बहनों ने आत्मबलिदान दिया था। संगीत की इन कलाधारिणी बहनों के सम्मान में वडनगर के ताना-रीरी समाधि स्थल पर वर्ष 2003 से हर वर्ष ताना-रीरी शास्त्रीय संगीत महोत्सव आयोजित होता है।

बिहार की सत्ता का नया समीकरण: जब गृह मंत्रालय ने बदल दी पूरी राजनीति की धुरी

(जीएनएस)। बिहार इस समय एक ऐसे राजनीतिक मोड़ से गुजर रहा है, जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक राज्य की सत्ता संरचना और राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगी। नई एनडीए सरकार के गठन के बाद विभागों का बंटवारा भले ही एक प्रशासनिक प्रक्रिया लगे, लेकिन इस बार जो हुआ, वह किसी साधारण फेरबदल से कहीं बड़ा और गहरा है। दो दशक तक बिहार की सत्ता का केंद्र माने जाने वाला गृह विभाग मुख्यमंत्री के हाथों से निकलकर सीधे-सीधे एनडीए सहयोगी दल बीजेपी के नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है। यह वही विभाग है जिसे अब तक बिहार में सत्ता की चाबी कहा जाता था, और जिसे नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक सफर में कभी अपने हाथ से जाने नहीं दिया था। लेकिन इस बार अचानक यह मंत्रालय किसी और के पास चला गया और यहीं से बिहार की राजनीति की नई कहानी शुरू होती है—एक ऐसी कहानी जिसमें जो दिख रहा है, वह सिर्फ आधा सच है, और जिसकी असली परतें चुनावी रणनीति, सत्ता की मजबूरियाँ और पार्टी की भविष्य की दिशा से जुड़ी हैं।

नई सरकार में गृह विभाग का सम्राट चौधरी को मिलना एक ऐसा राजनीतिक संकेत है जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि 2025 और 2029 तक की लंबी राजनीति को परिभाषित करेगा। सम्राट चौधरी को बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ा रही है, उससे साफ है कि पार्टी बिहार में अब सिर्फ सत्ता का साझेदार भर नहीं बनना चाहती, बल्कि अपने दम पर एक मजबूत राजनीतिक ध्रुव के रूप में उभरना

चाहती है। यही कारण है कि जिस विभाग से सत्ता चलती है, वह पहली बार बीजेपी के हाथ में आया है। इसका असर नीतीश कुमार के राजनीतिक कद पर भी होगा और उनके फैसलों की सीमा पर भी। अब बिहार में कानून-व्यवस्था से जुड़े हर अहम निर्णय उपमुख्यमंत्री कार्यालय से निकलेंगे। ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर पुलिसिंग और प्रशासनिक कार्रवाई तक—गृह मंत्रालय का दायरा इतना व्यापक है कि जो इस विभाग का नियंत्रण रखता है, वही राज्य की असली कमान संभालता है। नीतीश कुमार के लिए यह बदलाव सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक यात्रा की दिशा बदलने जैसा है। दो दशक से अधिक समय तक बिहार की नौकरशाही, शिक्षा, उद्योग, कानून, और सामाजिक सुधारों के अधिकांश फैसले उनके ही हस्ताक्षर से निकलते रहे। लेकिन इस बार उन्होंने स्वयं वह विभाग छोड़ दिया जो उनकी पहचान, उनकी शक्ति और उनके शासन की रीढ़ माना जाता था। यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि गठबंधन की मजबूरी और बदलती परिस्थितियों ने मुख्यमंत्री को यह कदम उठाने के लिए विवश किया। लेकिन इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नीतीश अब भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में अपनी भूमिका को पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रख पाएंगे। धीरे-धीरे वे प्रशासनिक चेहरा तो रहेंगे, लेकिन सत्ता के वास्तविक केंद्र से उनका हस्तक्षेप कम होता जाएगा। उधर बीजेपी इस फैसले से उत्साहित है। पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में "अवध और मगध जीतने" का जो नारा दिया था, वह अब सिर्फ नारा नहीं रह गया है। गृह विभाग का मिलना इस लक्ष्य के लिए एक बड़ी शुरुआत है। पार्टी के भीतर सम्राट चौधरी को एक तेजस्वी और आक्रामक नेता के रूप में देखा जाता है। वह संगठन और सत्ता दोनों में मजबूत भूमिका निभाते हुए पार्टी को बिहार के उपेक्षित ब्राह्मण-वर्णी और ओबीसी वोट बैंक के बीच बड़ा चेहरा बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उनका कद अगले कुछ महीनों में और बढ़ेगा और संभव है कि आने वाले चुनावों में वे बीजेपी के मुख्य चेहरे के रूप में उभरें। विभागों के बंटवारे से एक और संकेत भी मिलता है—एनडीए के भीतर बीजेपी अपनी रणनीतिक स्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। भूमि-राजस्व, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, पशुपालन, श्रम—लगभग सभी महत्वपूर्ण और संसाधन-समृद्ध विभाग बीजेपी के नेताओं को मिले हैं। इससे सरकार का वास्तविक प्रशासनिक ढांचा भी बीजेपी केंद्रित हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और अन्य सहयोगी दलों को भी महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, लेकिन सत्ता की धुरी अब CM हाउस और BJP ऑफिस के बीच कहीं संतुलित होते हुए दिख रही है।अगले कुछ महीनों में यह परिवर्तन बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा। कानून-व्यवस्था को लेकर हर छोटा-बड़ा निर्णय अब स्पष्ट रूप से बीजेपी की प्राथमिकताओं और कार्यशैली को दिखाएगा। प्रशासनिक फैसलों में भी पार्टी की पकड़ धीरे-धीरे मजबूत होगी। यह बदलाव न केवल राज्य की नौकरशाही पर असर डालेगा, बल्कि सत्ता के भीतर समीकरण और गठबंधन की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव छोड़ेगा। नीतीश कुमार का यह कदम उनकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है या राजनीतिक परिपक्वता का संकेत है—इस पर बहस जारी है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में शक्ति का नया संतुलन बन चुका है। गृह मंत्रालय ने इस बार न सिर्फ विभाग बदले हैं, बल्कि बिहार की सत्ता की आत्मा को नई दिशा दे दी है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई—यह तो आने वाले अध्याय का प्रस्तावना भर है, और असली राजनीतिक नाटक आने वाले महीनों में सामने आएगा।

शेयर बाज़ार के नाम पर भरोसा तोड़ा: रिटायर्ड कैप्टन से 32 लाख की साइबर ठगी ने खोला ऑनलाइन निवेश का खतरनाक चेहरा

(जीएनएस)। नोएडा में एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन के साथ हुआ 32 लाख 25 हजार रुपये का साइबर फ्रॉड एक बार फिर यह याद दिलाता है कि डिजिटल युग में ठगों की दुनिया कितनी संगठित, तकनीकी और खतरनाक हो चुकी है। सेक्टर-37 के निवासी कैप्टन दमन दत्ता, जो सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि एक साधारण-सा व्हाट्सएप मैसेज उनके वर्षों की बचत को निगल जाएगा। 15 सितंबर को उनके मोबाइल पर आई एक महिला की प्रोफ़ाइल, जो खुद को नीतिका भल्ला नाम से परिचित कराती है, बेहद व्यवस्थित तरीके से तैयार किए गए स्कैम की शुरुआत थी। महिला ने आत्मविश्वास से दावा किया कि वह एसबीआई सिक्योरिटीज की ब्लॉक ट्रेडिंग स्कीम की सलाहकार है और इसमें निवेश करने पर खाताधारक को भारी मुनाफा मिलता है।

कैप्टन दमन दत्ता ने जब इस प्रस्ताव पर संदेह जताया तो ठगों ने अपनी 'काबिलियत' साबित करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने ऐसा पोर्टल भेजा जिसमें एसबीआई सिक्योरिटीज का लोगो, कंपनी की रंग-योजना और यहां तक कि सीईओ सुरेश शुक्ला की फोटो भी लगी थी। हर चीज़ इतनी वास्तविक दिखती थी कि एक आम उपयोगकर्ता ही नहीं, अनुभवी व्यक्ति भी इसे असली मान ले। पहले 25 हजार रुपये का निवेश कराए जाने के बाद पोर्टल पर कृत्रिम रूप से दिखाया गया मुनाफा मानो विश्वास जीतने का जाल था। दमन दत्ता ने पहले देखा कि उनका पैसा बढ़ रहा है—वास्तव में नहीं, बल्कि स्क्रीन पर एक बनाए गए डैशबोर्ड पर।

ठगों का मकसद साफ था—विश्वास हासिल करो और फिर उसे पूँजी में बदल दो। यही वजह रही कि अगले दस दिनों में यानी 25 सितंबर तक दमन दत्ता ने अलग-अलग खातों में कुल 32 लाख 25 हजार रुपये जमा कर दिए। हर बार निवेश के बाद दिखाए जा रहे 'मुनाफे' ने उनके मन में भरोसा और गहरा कर दिया। लेकिन जैसे किसी स्कैम की पटकथा में होता है, असली मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने ही पैसे निकालने की कोशिश की।

जैसे ही उन्होंने रिफंड का अनुरोध किया, ठगों ने एक नया खेल शुरू किया—टैक्स, प्रोसेसिंग फीस और कई अजीबोगरीब शुल्कों के नाम पर 38 लाख रुपये और जमा करने की मांग रख दी। यह सुनते ही दमन दत्ता को शक हुआ कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। जब उन्होंने पोर्टल का तकनीकी परीक्षण कराया और विवरणों का मिलान किया, तो यह स्पष्ट हो गया कि पूरा प्लेटफ़ॉर्म ही नकली था। एसबीआई सिक्योरिटीज से इसका कोई लेना-देना नहीं था। धोखाधड़ी का पता चलते ही उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपर पुलिस उपायुक्त (साइबर क्राइम) शैव्या गोयल ने बताया कि इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस की पहली कोशिश यह है कि यह पता लगाया जाए कि भेजी गई रकम किन खातों में गई और इन खातों को कौन संचालित कर रहा था। इस प्रकार के मामलों में अक्सर पैसे कई खातों और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए तुरंत आगे बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे नेटवर्क पकड़ना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन पुलिस टीम डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेल को ट्रैक कर रही है। यह घटना उन हजारों निवेशकों के लिए एक चेतावनी है जो घर बैठे मुनाफा कमाने के नाम पर किसी भी लिंक या व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा कर लेते हैं। साइबर ठग बेहद पेशेवर तरीके से असली कंपनियों की वेबसाइटों की हूबहू नकल बनाते हैं, कर्मचारियों के नाम का दुरुपयोग करते हैं और वॉइस मैसेज, वीडियो कॉल और फर्जी कस्टमर सपोर्ट तक तैयार कर लेते हैं। उनका उद्देश्य एक ही होता है—विश्वास हासिल करना और फिर पैसा साफ कर देना।

भावनगर का सन्नाटा तोड़ देने वाली रात: जब एक अफसर बना अपनी ही परिवार का ख़ूनी

(जीएनएस)। गुजरात के भावनगर शहर की शांत गलियों में पिछले कुछ दिनों से छाया एक अजीब सा सन्नाटा है। यह वह सन्नाटा है जो किसी हादसे के बाद नहीं, बल्कि एक ऐसी हैवानियत के बाद पैदा होता है जिसमें इंसान अपनी ही आत्मा से नज़रें नहीं मिला पाता। वन विभाग के सहायक वन संरक्षक शैलेश खंभला की गिरफ्तारी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। चार दीवारों के भीतर पनपी वह काली रात अब पूरे प्रदेश में दहशत की कहानी बन चुकी है।

यह कहानी एक परिवार, एक भरोसे और एक पिता के उस रूप की है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शैलेश खंभला की पत्नी नयना और उनके दो मासूम बच्चे—13 साल की बेटी प्रीता और 9 साल का बेटा भव्य—कुछ दिन पहले तक ज़िंदा थे, हँसते थे, साझा सपने देखते थे। लेकिन अब वे तीनों भावनगर के उसी घर के पीछे बने मिट्टी के ढेर में दफन मिले, जिसे वे अपना घर कहते थे।

शैलेश खंभला पर आरोप है कि उसने न सिर्फ अपने परिवार की हत्या की, बल्कि उस अपराध को इतना सोच-समझकर, इतनी बारीकी से अंजाम दिया कि किसी

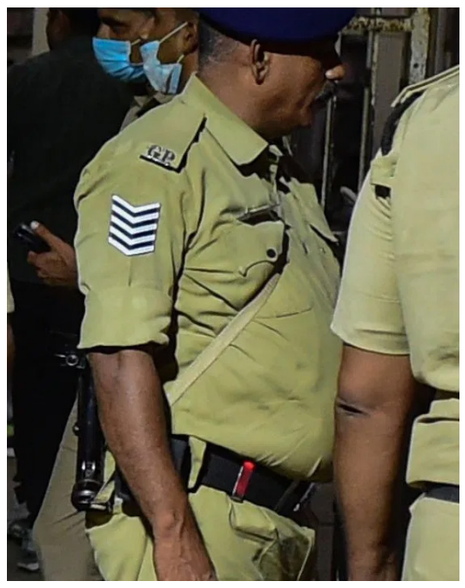

को संदेह न हो। जांच में खुलासा हुआ कि वह पिछले चार साल से अपनी ही विभाग की एक महिला कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध में था। यह रिश्ता धीरे-धीरे उसकी जिंदगी पर इस कदर भारी पड़ने लगा कि उसने पत्नी और बच्चों को ही "रास्ते से हटाने" का फैसला कर लिया।

जिस घर में कभी बच्चे खेलते थे, उसी घर के पिछवाड़े उसने दो गहरे गड्ढे खुदवाए। अपने जूनियर अधिकारी गिरीश वानिया से कहा—कचरा फेंकने के लिए। बाद में नीलगाय गिरने की कहानी गढ़कर उन गड्ढों को बंद करवाने के लिए डंपर भी मंगवाया। यह सब एक ऐसे आदमी ने किया जो कानून का रक्षक माना जाता है, जो जंगल की रक्षा करता है, जिसे प्रकृति ने जिम्मेदारी दी थी। लेकिन उसने वही हाथ अपराध के लिए इस्तेमाल किए।

जांच में जब उसके कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, उसके बयान उलझते गए, उसके चेहरे की बेरुखी और परिवार के प्रति ठंडा रवैया दिखाई दिया—तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि यह कहानी उसी के घर से शुरू होकर उसी घर में खत्म होती है। 16 नवंबर को जब पुलिस ने घर के पीछे खुदे गड्ढों को खोला, तो मिट्टी में दबी वह सच्चाई सामने आई जिसने हर किसी के दिल को दहला दिया। वहीं पड़ी थीं नयना, प्रीता और छोटा भव्य—तीन लाशें, तीन कहानियाँ, तीन ज़िंदगियाँ।

पूछताछ में शैलेश टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने रात के अंधेरे में तकिये से गला दबाकर पत्नी और बच्चों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद पत्नी के मोबाइल से खुद को एक मैसेज भेजा—"मैं किसी और के साथ जा रही हूँ"—ताकि सबको लगे कि यह परिवार स्वेच्छा से चला गया। फोन को एयरप्लेन मोड में डालकर उसने लापता होने की चालाक तस्वीर बनाई। पर अपराध का सच उतना ही गहरा था जितना उसने खुदवाया हुआ गड्ढा।

नयना लंबे समय से चाहती थीं कि परिवार एक साथ रहे। लेकिन शैलेश के दिल में कोई और बस चुका था। वैवाहिक कलह बढ़ती गई, और अंततः वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को दुश्मन समझ लिया, अपने ही बच्चों को बोझ मान लिया।

भावनगर आज भी इस घटना से उबर नहीं पाया है। लोग पूछ रहे हैं—एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है? एक अफसर जिसके कंधों पर प्रकृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, वह अपने ही परिवार की रक्षा क्यों नहीं कर सका? क्या एक अवैध रिश्ता किसी इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वह खून को मिट्टी में दबाने लगे?

यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह उस समाज का आईना है जहाँ रिश्ते टूटने पर संवाद की जगह हिंसा ले लेती है, जहाँ मानसिक तनाव की पहचान नहीं की जाती, जहाँ परिवारों के दर्द अनकहे रह जाते हैं और कभी-कभी इस तरह फट पड़ते हैं कि पूरी दुनिया हिल जाती है।

जांच जारी है, कोर्ट में मामला चलेगा, कानून अपने तरीके से सज़ा तय करेगा। पर भावनगर के लोग शायद बहुत लंबे समय तक उस घर के पिछले हिस्से में पड़े गड्ढों को भूल नहीं पाएंगे। वे गड्ढे सिर्फ मिट्टी के नहीं थे, वे एक परिवार के सपनों की कब्र बन गए।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा पुनर्निर्मित कम्युनिटी हॉल का भव्य उद्घाटन एवं कर्मचारियों को समर्पण

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के पुनर्निर्मित एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त कम्युनिटी हॉल का आज 21 नवम्बर 2025 (शुक्रवार) को मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस कम्युनिटी हॉल को आधिकारिक रूप से रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के उपयोग हेतु समर्पित किया। अपने संबोधन में श्री वर्मा ने कहा कि "यह कम्युनिटी हॉल कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र सिद्ध होगा।"

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया की कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन उपस्थित रहे एवं कम्युनिटी हॉल के पुनर्निर्माण को महत्व बताते हुए कर्मचारियों के हित में उठाए गए इस कदम की सराहना की। ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी संबोधन दिया और इस सुविधा को कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

कम्युनिटी हॉल की प्रमुख विशेषताएँ

हॉल में 10 नए एयर कंडीशनर (AC) लगाए गए हैं। विवाह/पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक वर–वधू कक्ष निर्मित किए गए हैं। बड़े आयोजनों हेतु सभा मंडप विकसित किया गया है। परिसर के बाहर सुंदर हरित उद्यान (गार्डन) विकसित किया जा रहा है। रीनोवेशन अवधि के बाद कम्युनिटी हॉल की बुकिंग पुनः प्रारंभ हो चुकी है।

सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के बावजूद यह कम्युनिटी हॉल रेलवे कर्मचारियों के लिए 4000 प्रतिदिन की किफायती दर पर उपलब्ध रहेगा, जो निजी आयोजनों के लिए अत्यंत सुलभ है।

उद्घाटन समारोह में मंडल के कर्मचारी एवं अधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह संपूर्ण कार्यक्रम वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

सोनभद्र में खनन का काला सच: सुरक्षा लापरवाही ने ली सात जानें, एसआईटी ने की बड़ी कार्रवाई

(जीएनएस)। सोनभद्र में 15 नवंबर को हुए दर्दनाक खनन हादसे ने सिर्फ सात मजदूरों की जान ही नहीं ली, बल्कि पूरे क्षेत्र की खनन व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को लेकर लंबे समय से उठते सवालों को फिर एक बार केंद्र में ला दिया। ओबरा क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी स्थित कृष्णा माइनिंग वर्क्स में उस दिन सामान्य की तरह ड्रिलिंग का काम चल रहा था, लेकिन मजदूरों के लिए यह सामान्य दिन नहीं था। पहाड़ी के भीतर लगातार हो रही गहरी ड्रिलिंग ने चट्टान की प्राकृतिक संरचना को इतना कमजोर कर दिया था कि एक तेज़ झटके के साथ उसका भारी हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा और मजदूर कुछ ही पलों में मलबे के नीचे दब गए। चीखें, अफरातफरी, धूल और टूटे पत्थरों की अंधी बरसात के बीच जो बच पाया, उसने बताया कि मजदूर बार-बार यह चेतावनी दे रहे थे कि नीचे की परत अब सुरक्षित नहीं रही, मगर उस चेतावनी को ठेकेदारों के दबाव और उत्पादन के बढ़े लक्ष्य ने निगल लिया।

घटना के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने एक विशेष जांच दल का गठन किया, जिससे साफ हो गया कि प्रशासन इस हादसे को किसी सामान्य दुर्घटना की तरह नहीं देखने वाला। एसआईटी की जांच कई दिनों तक चली, जिसमें रिकॉर्ड, ड्रिलिंग लॉग, मजदूरों के बयान और साइट पर मिले साक्ष्यों को एक साथ देखकर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हादसा कोई अचानक हुई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, बल्कि मानव लापरवाही की वह श्रृंखला थी जो लंबे समय से खदान में चल रही थी। जांच ने यह भी उजागर किया कि नियमों के मुताबिक जिस गहराई और कोण पर ड्रिलिंग की अनुमति होती है, उससे कहीं अधिक गहराई में काम कराया जा रहा था, ताकि उत्पादन तेज़ हो सके। विस्फोटक के उपयोग को लेकर भी खदान प्रबंधन ने जरूरी मानकों का पालन नहीं किया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि माइंस मैनेजर अनिल कुमार झा को सुरक्षा की स्थिति का आकलन करने के बाद खान सुरक्षा निदेशक, लखनऊ को लिखित सूचना देनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं किया गया। मजदूरों के बार-बार मना करने के बावजूद उन्हें खतरनाक हिस्से में उतरने के लिए मजबूर किया गया। यह दबाव इतना अधिक था कि कई मजदूर घटना से कुछ घंटे पहले ही यह कहकर वापस निकल आए थे कि चट्टान में अजीब-सी दरारें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुनाफे की भूख ने इन चेतावनियों को धूल की तरह झाड़ दिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने माइंस मैनेजर अनिल कुमार झा, स्टाफ अजय कुमार, गौरव सिंह और माइंस मेट चन्द्रशेखर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

यह कार्रवाई उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की तरह है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, लेकिन यह उम्मीद तभी पूरी होगी जब खनन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों पर सिर्फ कागज़ पर नहीं, जमीन पर भी सख्ती से अमल होगा। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है और जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उन सभी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे हादसे ने सोनभद्र के खनन तंत्र को आईना दिखाया है। खदानें वर्षों से रोजगार का बड़ा स्रोत रही हैं, लेकिन इसके साथ यह भी सच्चाई है कि खनन कंपनियों और ठेकेदारों की लापरवाही अक्सर मजदूरों की जान पर भारी पड़ती रही है। इस त्रासदी ने फिर एक बार याद दिलाया है कि खदानों में काम करने वाला मजदूर सिर्फ उत्पादन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसकी जान की कीमत किसी लाभ से बड़ी होनी चाहिए।

जगुदन स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के जगुदन स्टेशन यार्ड में 23.11.2025 (रविवार) को ब्रिज संख्या 983 के पुनर्निर्माण कार्य के संबंध में ब्लॉक लिया जा रहा है। जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जो निम्नानुसार है:-

पूर्णतः रद्द ट्रेन

▸▸ दिनांक 23.11.2025 की ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

▸▸ दिनांक 24.11.2025 की ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

आंशिक रद्द ट्रेनें:

▸▸ दिनांक 23.11.2025 की ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड-वडनगर-वलसाड एक्सप्रेस वडनगर और गांधीनगर कैपिटल के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रिशेड्यूल ट्रेनें:

1. दिनांक 23.11.2025 की ट्रेन संख्या 20485 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस जोधपुर से 2 घंटे रिशेड्यूल होगी।
2. दिनांक 23.11.2025 की ट्रेन संख्या 69207 गांधीनगर कैपिटल–वरेठा मेमू गांधीनगर कैपिटल से 01 घंटा रिशेड्यूल होगी। रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें। यात्री ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते है।

24 नवम्बर को पालीताना से बान्द्रा टर्मिनस के लिए चलेगी "स्पेशल ट्रेन" टिकटों की बुकिंग 22 नवम्बर (शनिवार) से शुरू होगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं उनकी सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से पालीताना और बांद्रा टर्मिनस स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर "सुपेशल ट्रेन" चलाई जाएगी। इस ट्रेन का एसएलआरडी कोच अनारक्षित होगा, जिसके लिए टिकट यूटीएस काउंटर से मिलेगा तथा इस कोच में सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस का किराया लगेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इस ट्रेन का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09009/09010 बांद्रा टर्मिनस-पालीताना सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 09009 बांद्रा टर्मिनस-पालीताना सुपरफास्ट स्पेशल रविवार, 23 नवम्बर, 2025 को 19:25 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन

सुबह 09:25 बजे पालीताना पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09010 पालीताना-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार, 24 नवम्बर, 2025 को पालीताना से 20:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10:45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड़, नवसारी, सूरत, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, बोटाद, धोला, सोनगढ़ और सिहोर (गुजरात) स्टेशनों पर रूकेगी। इस ट्रेन में थर्ड एसी और स्लीपर कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09009/09010 की बुकिंग 22 नवम्बर, 2025 (शनिवार) से सभी पीआरएस काउंटरों और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अदाणी समूह का बड़ा एग्ज़िट: AWL में बची पूरी हिस्सेदारी बेचकर एफएमसीजी सेक्टर से बाहर, बाजार में तेज़ हलचल

(जीएनएस)। अदाणी समूह द्वारा अदाणी विल्मर एग्री बिजनेस लिमिटेड (AWL) में अपनी बची हुई सम्पूर्ण हिस्सेदारी बेचने के बाद बाजार में हलचल बढ़ गई है। शुक्रवार को हुई इस ब्लॉक डील ने न सिर्फ एग्ज़िट की घोषणा को औपचारिक रूप दिया, बल्कि इसने एफएमसीजी सेक्टर में समूह की दो दशकों से चली आ रही उपस्थिति को भी समाप्त कर दिया। सुबह जब बाजार खुला, तब AWL के शेयर 280.70 रुपये की कीमत पर ट्रेड हुए, लेकिन कुछ ही घंटों में बिकवाली के भारी दबाव ने शेयर को 266.45 रुपये के निम्न स्तर तक ला दिया। लगभग 6 प्रतिशत की इस तेज गिरावट ने निवेशकों को संकेत दिया कि सौदे का झटका शेयर मूल्य पर सीधा असर डाल चुका है। बाजार सूत्रों का अनुमान है कि ब्लॉक डील का कुल मूल्य 2,500 करोड़ रुपये के आसपास रहा, हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।

इस सौदे में दिलचस्प बात यह रही कि घरेलू और विदेशी—दोनों तरह के संस्थागत निवेशकों ने एक साथ इस हिस्सेदारी के लिए हाथ बढ़ाया। वैनगार्ड, चार्ल्स श्वाब, एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा एमएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ, क्वांट एमएफ, बंधन एमएफ जैसे बड़े घरेलू संस्थान इस खरीद का हिस्सा रहे। इसके अलावा सिंगापुर, यूएई और अन्य एशियाई देशों के अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी इस क्लीन-आउट ब्लॉक डील में शामिल हुए। इससे बाजार ने साफ संकेत पाया कि AWL जैसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता व्यवसाय में निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत है, भले ही अदाणी समूह इससे अलग हो गया हो।

पिछले कुछ दिनों से यह सौदा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में समूह ने 13 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर अपनी स्थिति 7 प्रतिशत तक घटा ली थी। अब शेष 7 प्रतिशत हिस्सा बेचकर समूह ने इस संयुक्त उपक्रम से पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला अंतिम रूप दिया।